श्रीमती सविता शारदा : सभापति महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि 21-3-2002 को मंत्री महोदय ने लोक सभा में इसी प्रश्न में बताया था जैसाकि अभी मंत्री जी ने बताया कि मिलिट्री स्कूल्, राष्ट्रीय इंडियन कॉलेज , आर. आई. एम.सी और एन.सी.सी. तथा होमगार्ड के अन्तर्गत इन्हें ट्रेंनिग मिल रही है । और अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि 13 लाख स्टूडेंट्स इसमें ट्रेंनिग ले रहे हैं । मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं कि पूरे भारत में ऐसे कितने ट्रेनिंग कॉलेजिज हैं ? अभी मुझे बाहर जाने का अवसर प्राप्त हुआ । वहां कालेज स्टूडेंटस को कॉलेज लैवल के बाद कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिग दी जाती है ताकि वे देश के लिए काम कर सकें । जो नैचुरल कैलामिटिज आती है । , उसमें भी वे अपना सहयोग दे सकेंगे । क्या मंत्री महोदय युवा वर्ग के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग कंफ्लसरी करेंगे ? क्या आपकी नीति में इस प्रकार की कोई व्यवस्था हैं ?

प्रो. चमन लाल गुप्ता : जहां तक मिलिट्री ट्रेंनिग का सवाल है , वह तो हमने इस प्रश्न के उत्तर में ही कहा है कि वह संभव नहीं है । उसके दो कारण हैं । एक तो यह डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसके अंदर हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वह कौन सा प्रोफैशन अडॉप्ट करें और दूसरा इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है । अगर सिर्फ दो करोड़ यूथ्स को हमें ट्रेन्ड करना हो तो उसमें 20 हजार करोड़ रूपए तुरंत चाहिए ओर रिकरिंग खर्च लगभग 10 हजार करोड़ रूपये का है । इस प्रकार से 40 करोड़ विद्यार्थी जो हमारे यूथ्स है , उनको अगर मिलिट्री देनी पड़े तो उसमे कितनी कॉस्ट आ सकती है, इसका आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए ।

श्री सभापति : श्रीमती बिम्बा रायकर । अनुपस्थित । प्रश्न संख्या 44

आई .डब्लयू डी.पी , डी.पी.ए.पी , डी.डी.पी. तथा टी.टी.ई.टी के तहत हिमाचल प्रदेश को धन राशि

*44. **श्री कृपाल परमार :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के तहत क्रियान्वित समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्लयू.डी.पी) सूख प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी) मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी) एवं प्रौघोगिकी विकास , विस्तार तथा प्रशिक्षण (टी.डी.ई.टी) के अधीन हिमाचल प्रदेश को गत दो वर्षो मे कितनी राशि प्रदान की गई : और

(ख) इस राशि का राज्य सरकार ने किस प्रकार सदुप्रयोग किया ?

ग्रामीण विकास मंत्री (**श्री काशी राम राणा**) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई. डब्लयू.डी.पी) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) और प्रौघोगिकी विकास , विस्तार तथा प्रशिक्षण (टी.डी.ई.टी.) योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को गत दो वर्षो दौरान उपलब्ध करायी गई केन्द्रीय सहायता की राशि निम्नानुसार हैः

योजना का नाम	वर्ष	
	2001-2003	2002-2003
	(करोड़ रूपये में)	
समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई . डब्लयू.डी.पी)	10.36	15.00
सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी)	3.17	3.71
मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी)	5.14	8.51
प्रौघोगिक विकास, विस्तार तथा प्रशिक्षण योजना (टी.डी.ई.टी.)	1.37	0.55
योग	20.04	27.77

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्लयू .डी.पी) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) , तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.पी.पी) के अन्तर्गत जारी की गई निधियों का उपयोग ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उपबन्धों के अनुसार किया जा रहा है । प्रौघोगिक विकास, विस्तार तथा प्रशिक्षण (टी.डी.ई.टी.) योजना के अन्तर्गत जारी की गई निधियोंका उपयोग इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं के संबंध में किए गए प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा हैं ।

Funds to Himachal Pradesh under IWDP, DPAP, DDP and TDET

†*44. SHRI KRIPAL PARMAR: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the amount provided to Himachal Pradesh during the last two years under the Integrated Wasteland Development Programme (IWDP),

†Original notice of the question was received in Hindi.

Drought Prone Area Programme (DPAP), Desert Development Programme (DDP) and Technology Development Extension and Training (TDET) implemented under the control of Land Resources Department of Rural Development Ministry; and

(b) the manner in which the State Government have utilized this amount?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI KASHIRAM RANA):(a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The amount of Central assistance provided to Himachal Pradesh during the last two years under the Integrated Wasteland Development Programme (IWDP), Drought Prone Areas Programme (DPAP), Desert Development Programme (DDP) and Technology Development Extension and Training (TDET) Scheme are as given below:-

(Rs. in crore)

Name of Schemes	Years	
	2001-2002	2002-2003
IWDP	10.36	15.00
DPAP	3.17	3.71
DDP	5.14	8.51
TDET	1.37	0.55
TOTAL:	20.04	27.77

(b) As per inforamtioh received from Govt, of Himachal Pradesh, funds released under IWDP, DPAP AND DDP are being utilized as per provisions of the Guidelines for Watershed Development issued by the Ministry of Rural Development. Funds released under TDET are being utilized as per provisions of the sanctioned projects under the Scheme.

श्री कृपाल परमार : माननीय सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश हिमखंडों और हिम नदियों का प्रदेश है । यहां से बहने वाली नदियों से पंजाब , हरियाणा और यहां तक कि राजस्थान को सिंचाई कि लिए पानी मिलता है । लेकिन हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं । हमारे में नदियों से पानी उठाकर ऊंचे पहाड़ों पर खेतों में

पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है । मंत्री जी ने अपने जवाब में जो आंकड़े दिये हैं, उसमें 2001-2002 में 20 करोड़ रूपए और 2002-2003 में लगभग 28 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हिमालय प्रदेश की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस राशि को बढ़ाने का क्या वे प्रावधान करेंगे ?

श्री काशीराम राणा : माननीय सभापति महोदय, देश के विभिन्न राज्यों में जो भी परिस्थिति पैदा होती है , उसको ख्याल में रखकर जो भी वहां से डिमांड आती है , उसके अनुसार ठीक ढंग से हम फंड अलॉट करते रहते हैं । जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है , अगर वहां कोई विशेष परिस्थिति हो और उस परिस्थिति में इस बारे में हमारे पास कोई प्रस्ताव आएगा तो हम अवश्य इसके बारे में सोचेंगे ।

श्री कृपाल परमार : महोदय, हिमाचल प्रदेश में नार्थ ईस्ट के बाद सबसे ज्यादा बारिश होती है लेकिन यहां पर रेन हारवैस्टिंग से पानी को इक्ट्ठा करके सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की क्या सरकार कोई योजना बनाएगी और इसका "ख " भाग है कि जब तक इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की भागीदारी नहीं होगी, यह काम सफल नहीं हो पाता है । क्या सरकार ऐसी योजना बनाएगी कि रेन हारवैस्टिंग के कार्यक्रम में लोगों की भागादारी सुनिश्चित करे ।

श्री कांशीराम राणा : माननीय सभापति महोदय, हमारी जो भी योजनाएं अभी चल रही हैं , चाहे वॉटरशेड स्कीम हो या रेन हारवैस्टिंग की योजना हो , हम बहुत बड़े पैमाने पर योजनाओं को लेते हैं । इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी जी ने स्वजल धारा योजना भी उसके अंतर्गत चलाई है । माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है , इसके बारे में हमने रिप्लाई किया है । पानी के बारे में अगर कोई समस्या हो तो जैसा मैंने पहले जवाब दिया है कि हम अवश्य उसके बारे में पॉज़िटिवली सोचेंगे ।

*45. [The questioners (SHRI KALRAJ MISHRA and DR. AKHILESH DAS): were absent, for answer *vide* page 297

Low cost housing for textile workers

*46. SHRIMATI S.G. INDIRA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have taken up building of low cost houses for textile workers;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?